2021

April - June

DETECTIVE

केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, गाज़ियाबाद

CENTRAL DETECTIVE TRAINING INSTITUTE, GHAZIABAD

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT, MHA, GOVT. OF INDIA

Index

Sl. No.		Page No.
1	राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और हिंदी के प्रचार–प्रसार के माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का संदेश	1
2	The Role of Policemen is to ensure a civilized and Peaceful Society	2
3	Training Actives of SDTI, Ghaziabad	3
4	Other Activities	4

संपादक मण्डल

मुख्य संरक्षक

श्री अम्बर किशोर झा. भा.पु.से.
निदेशक, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान,
गाज़ियाबाद (उ.प्र.)

संरक्षक

श्री विरेन्द्र कुमार, उप–प्राचार्य
केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान,
गाज़ियाबाद

संपादक

श्री बीरेन्द्र कुमार,
हिंदी प्रभारी अधिकारी

सहसंपादक

श्रीमती इन्दिरा कौशिक,
वरिष्ठ निजी सचिव

समन्वय

श्रीमती प्रियंका रावत,
निरीक्षक

सहायक

कु. रचना, आशुलिपिक

नोट

इस पत्रिका में प्रकाशित की गई रचनाएं और विचार लेखकों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। रचना की मौलिकता व अन्य किसी विवाद के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

From Director's Desk

I am delighted to bring out the second edition of CDTI, Bulletin 'Detective' from April to June, 2021 which highlights our achievements and some of the major activities undertaken at this institute during the period.

CDTI, Ghaziabad is imparting training to the in-service officers of the State Police, Judicial Officers, Public Prosecuting Officers and CAPFs. During this quarter total 22 courses were conducted in online mode in which 602 officers were trained. CDTI took an initiative to organize an interactive webinar on "Women Safety and Cyber Crime" for the girl students of schools and colleges, which was widely appreciated by the participants.

Despite the COVID-19 pandemic and lockdown, all the officers and staff remained committed to their duties and strictly followed the guidelines issued by MHA, Government of India and BPR&D Headquarters from time to time.

I welcome the feedback from the readers to help in improving the quarterly bulletins.

Ambar Kishor Jha, IPS
Director
CDTI, Ghaziabad

संपादक की कलम से

मेरे लिए यह व्यक्तिगत प्रसन्नता का विषय है कि वर्ष 2021 की तिमाही पत्रिका का दूसरा अंक प्रकाशित हो रहा है। विभागीय पत्रिका के माध्यम से मेरा यह प्रयास है कि राजभाषा हिंदी को लोकप्रिय बनाएं तथा राजभाषा संबंधी प्रावधानों के अनुरूप सरकारी कामकाज में इसका अधिक–से–अधिक उपयोग करें। राजभाषा हिंदी में काम करना हमारे सरकारी दायित्वों का एक अभिन्न अंग है। साथ ही यह मेरा विचार है कि गृह पत्रिकाएं अधिकारियों एवं कर्मचारियों में छिपी हुई सृजनात्मक प्रतिभाओं को उजागर करने का एक सशक्त माध्यम होती हैं।

इस पत्रिका के माध्यम से पिछले तीन महीनों के दौरान इस संस्थान में हुई विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों एवं विभिन्न समारोह की उपलब्धियों को प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है। यह अंक आप सभी पाठकों को इस विश्वास के साथ समर्पित है कि आप अपने अमूल्य विचारों से हमें अवगत कराएंगे जिससे पत्रिका के आगामी अंक में और निखार आएगा।

बीरेन्द्र कुमार
संपादक
हिंदी प्रभारी अधिकारी

राजभाषा विभाग,गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संघ की राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख दिशा-निर्देश

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें व सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रुप में (अंग्रेजी और हिंदी) जारी किए जाएं। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में तैयार, निष्पादित अथवा जारी किए जाएं।

2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों से हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है।

3. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत कार्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं।

4. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अनुसार केंद्र सरकार, ऐसे अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारुपण और अन्य उन शासकीय कार्यों को केवल हिंदी में करने के लिए आदेश जारी कर सकती है, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो।

5. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार सभी मैनुअल, संहिताएं और असांविधिक प्रक्रिया साहित्य, रजिस्टरों के प्रारुप और शीर्षक, नामपट्ट, साइन बोर्ड, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें भी हिंदी और अंग्रेजी (डिग्लॉट फॉर्मेट) में होंगी। तदनुसार, केंद्र सरकार के कार्यालयों से अपेक्षा है कि वे सभी मैनुअल, संहिताओं एवं प्रक्रिया संबंधी असांविधिक साहित्य से संबंधित अन्य प्रक्रियात्मक साहित्य अनुवाद के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में भेजें।

6. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम के प्रावधानों तथा इनके अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रुप से अनुपालन हो तथा इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त एवं प्रभावकारी जांच बिंदु बनाए जाएं।

7. अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न–पत्र को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्न–पत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाए और ऐसे प्रश्न–पत्र द्विभाषी रुप से, हिंदी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं। साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों को हिंदी में उत्तर देने की छूट दी जाए।

8. केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा सभी सेवाकालीन, विभागीय तथा पदोन्नत्ति परीक्षाओं में (अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षाओं सहित) अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में देने का विकल्प दिया जाए। प्रश्न–पत्र अनिवार्यतः दोनों भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी, में तैयार कराए जाएं। जहां साक्षात्कार लिया जाना हो, वहां अभ्यर्थियों को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हिंदी में देने की छूट दी जाए।

9. सभी प्रकार की वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में वैज्ञानिकों आदि को राजभाषा हिंदी में शोध पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। उक्त शोध पत्र संबंधित मंत्रालय/विभाग और कार्यालय आदि के मुख्य विषय से संबंधित हों।

10. 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में सभी प्रकार का प्रशिक्षण, चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, सामान्यतः हिंदी माध्यम से हो। 'ग' क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराई जाए और प्रशिक्षणार्थी की मांग के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाए।

11. केंद्र सरकार के कार्यालयों में जब तक हिंदी टंककों व हिंदी आशुलिपिकों से संबंधित निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिए जाते, तब तक उनमें केवल हिंदी टंकक व हिंदी आशुलिपिक ही भर्ती किए जाएं।

12. अंतरराष्ट्रीय संधियों और करारों को अनिवार्य रुप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाए। विदेशों में निष्पादित संधियों और करारों के प्रामाणिक अनुवाद तैयार करा कर रिकॉर्ड के लिए फाइल में रखे जाएं।

13. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित बैंकों की शाखाओं में निम्नलिखित कार्य हिंदी में किए जाएः–

    ग्राहकों द्वारा हिंदी में भरे गए आवेदनों और ग्राहकों की सहमति से अंग्रेजी में भरे गए आवेदनों पर जारी किए जाने वाले मांग ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सभी प्रकार की सूचियां, विवरणियां, सावधि जमा रसीदें, चैक बुक संबंधी पत्रादि, दैनिक बही, मस्टर रोल, प्रेषण बही, पास बुक, लॉग बुक में प्रविष्टियाँ, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, सुरक्षा एवं ग्राहक सेवा संबंधी कार्य, नये खाते खोलना, लिफाफों पर पते लिखना, कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, अवकाश, भविष्य निधि, आवास निर्माण अग्रिम, कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं संबंधी कार्य, बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त आदि।

14. हिंदीतर राज्यों में बोर्ड, साइन बोर्ड, नामपट्ट तथा दिशा संकेतकों के लिए क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी, इसी क्रम में, प्रयोग की जानी चाहिए।

15. अनुवाद कार्य तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनिवार्य अनुवाद प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अनुवाद के प्रशिक्षण के लिए नामित किया जा सकता है, जिन्हें स्नातक स्तर पर हिंदी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान हो तथा जिनकी सेवाओं का उपयोग कार्यालय द्वारा अनुवाद कार्य के लिए किया जा सकता है।

16. अनुवादकों को मानक शब्दकोश (अंग्रेजी–हिंदी, हिंदी–अंग्रेजी) तथा अन्य तकनीकी साहित्य और शब्दावलियों जैसी सहायक सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएं।

17. भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण के दौरान हिंदी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य रुप से दिया जाता है ताकि सरकारी कामकाज में वे इसका प्रयोग कर सकें। तथापि, अधिकांश अधिकारी सेवा में आने के पश्चात सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग नहीं करते। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों में सही संदेश नहीं जाता। परिणामस्वरुप, सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पाता। केंद्र सरकार के कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी तथा राजभाषा नीति के अनुपालन में गति मिलेगी।

18. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय अपने केंद्रीय सेवाओं के प्रशिक्षण संस्थानों में राजभाषा हिंदी में प्रशिक्षण की व्यवस्था उसी स्तर पर करें, जिस स्तर पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में कराई जाती है और अपने विषयों से संबंधित साहित्य का सृजन हिंदी में करवाएं, जिससे प्रशिक्षण के बाद अधिकारी अपना सरकारी कामकाज सुविधापूर्वक राजभाषा हिंदी में कर सकें। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम मल्टीमीडिया प्रॉजेक्टर, लैपटॉप आदि के माध्यम से आडियो/विजुअल रुप में तैयार कराए जाएं।

19. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का अपने कार्यालयों में व्यापक प्रचार–प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो।

20. विभिन्न कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में नए दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं. नए दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यशाला की न्यूनतम अवधि एक कार्य दिवस की होगी। कार्यशाला में न्यूनतम दो तिहाई समय कार्यालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में कार्य करने का अभ्यास करवाने में लगाया जाए।

21. प्रशिक्षण और कार्यशालाओं सहित राजभाषा हिंदी संबंधी कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में बैठने के लिए अच्छा व समुचित स्थान एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक तरह से कर सकें।

22. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय अपने दायित्वों से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने तथा अपने विषयों से संबंधित शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं जाएं।

23. हमें अपने कार्य–व्यवहार में आम जीवन में प्रचलित शब्दों के प्रयोग पर बल देना चाहिए ताकि सामान्य नागरिक सरकारी नीतियों/कार्यक्रमों के बारे में सरल हिंदी में जानकारी प्राप्त कर सकें।

24. केंद्र सरकार के कार्यालय अपने कार्यालय में हिंदी में कार्य का माहौल तैयार करने के लिए हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं। इन पत्रिकाओं में कार्यालय के सामान्य कार्यकलापों तथा उस कार्यालय के कामकाज से संबंधित मौलिक आलेख प्रकाशित किए जाएं। साथ ही राजभाषा नीति के प्रमुख प्रावधानों का भी उल्लेख अवश्य हो। केंद्र सरकार के कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन पत्रिकाओं के 'ई–वर्जन' तैयार करें और इन्हें राजभाषा विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट ू तंरईीं.हवअ.पदपर उपलब्ध कराए गए प्लेटफार्म "ई–पत्रिकापुस्तकालय" पर अपलोड करें ताकि गृह–पत्रिकाएं पाठकों को सहज तथा सरल तरीके से प्राप्त हो सकें।

25. केंद्र सरकार के कार्यालयों के कंप्यूटरों में यूनिकोड की सुविधा हो ताकि कंप्यूटरों पर हिंदी में भी काम किया जा सके।

26. यह देखा गया है कि अनेक विभागों द्वारा वेबसाइट पर या तो सूचना हिंदी में नहीं दी जाती या कुछ मामलों में यह पूर्णतया हिंदी में उपलब्ध नहीं है। अतः वेबसाइट हिंदी में विकसित और नियमित रुप से अद्यतित करवाएं।

27. कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा का संवर्ग गठित होना चाहिए, जो कि कुल पदों के अनुरुप हो। मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों के हिंदी पदाधिकारियों को केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के समान वेतनमान व पदनाम दिए जाएं।

28. राजभाषा विभाग द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से हर वर्ष कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए 5 दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद प्रशिक्षु कंप्यूटर पर हिंदी में काम कर सकेंगे। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट www-chti.rajbhasha.gov.inपर उपलब्ध है।

29. सभी मंत्रालय/विभाग हिंदी संगोष्ठी का आयोजन करें।

30. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा कोई भी गैर सरकारी संस्था केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत नहीं की गई है। राजभाषा विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र पहले से ही देश भर में काम कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण निःशुल्क देते हैं एवं राजभाषा पर विचार–विमर्श के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कार्यालय संबंधित कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ऑनलाइन दिए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अतः गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जा रहे राजभाषा के प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए सरकारी कोष से अनावश्यक धन खर्च करना उचित नहीं है।

31. राजभाषा विभाग द्वारा आधुनिक ज्ञान/विज्ञान की विभिन्न विधाओं में मौलिक रुप से हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने एवं राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "राजभाषा गौरव पुरस्कार" दिए जाते हैं। राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालय/विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट आदि, राष्ट्रीयकृत बैंक, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा हिंदी गृह पत्रिकाओं के लिए "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाते हैं। इन दोनों पुरस्कार योजनाओं की जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट ू तंरईीं.हवअ.पदपर उपलब्ध है।

32. राजभाषा विभाग ने अपनी वेबसाइट पर विभिन्न संस्थाओं के लिंक उपलब्ध कराए हैं जिनके माध्यम से इन संस्थाओं की शब्दावली देखी जा सकती है। इस संबंध में यदि कार्यालयों द्वारा कोई अपनी शब्दावली तैयार की गई है तो वे उसे राजभाषा विभाग से साझा करें ताकि अन्य कार्यालय भी लाभान्वित हो सकें।

33. राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर "ई–सरल हिंदी वाक्यकोश" शीर्षक के अंतर्गत सामान्यतः अंग्रेजी में प्रयोग होने वाले वाक्यों के हिंदी अनुवाद दिए गए हैं जिनके प्रयोग से अधिकारी फाइलों पर सामान्य टिप्पणियां आसानी से हिंदी में लिख सकते हैं।

34. केंद्र सरकार के कार्यालयों की मांग पर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा भी अनुवादकों को प्रशिक्षण देने के लिए इसी प्रकार के प्रबंध किए गए हैं।

35. केंद्र सरकार के कार्यालयों की मांग पर केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए सुझावों को पुनः बल दिया है दृ सरकारी हिंदी और सामाजिक हिंदी के अंतर को कम करना; देश की दूसरी भाषाओं से हिंदी को और समृद्ध करने के लिए उपाय करना दृ दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्दों को हिंदी में ग्रहण करना, दूसरी भारतीय भाषाओं से दस–दस अच्छे शब्दों को खोजकर हिंदी भाषा में जोड़ना; हिंदी में अनुवाद सरल भाषा में सुनिश्चित करना जिससे सरकारी भाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार में बाधक नहीं, सहायक हो।

36. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने हाल ही में भारत सरकार के सभी सचिवों/विभिन्न सरकारी संगठनों के प्रमुखों से आग्रह किया है कि जब वे प्रत्येक माह वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करें तो वे उनमें हिंदी में सरकारी काम–काज में हुई प्रगति की भी समीक्षा करें और अपने संगठन में राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करें। साथ ही, संयुक्त सचिव (प्रशासन)/संगठन के प्रशासनिक प्रमुख को हिंदी कार्यान्वयन का तथा वर्ष की प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाए।

EARTHQUAKE PREPAREDNESS AND RESPONSE

Aditya Pratap Singh
Deputy Commandant,
8th Battalion, NDRF,
Ghaziabad

History of earthquakes is older than Mankind. Since time immemorial, humans have been experiencing earthquakes. We have lived with this hazard for thousands of years but our vulnerability to its impact has increased drastically with the evolution of the dwelling pattern. Our ancestors resided in caves inside dense forests but we abandoned these natural habitats to settle initially in mud houses and finally in the dense forest of cement, mortar and concrete. This new habitat proved safer in terms of physical safety and comfort. Now we don't have to be watchful for a crouching tiger while sleeping. Moreover it saves us from rain & inclement weather. It protects us from almost all types of hazards up to a certain extent like loo, thunderstorms, snow blizzards and rains etc but not from the earthquakes. The risk of being trapped under the debris of a collapsed structure has increased manifold after shifting to this new habitat. Tremors are always terrifying phenomena but when somebody is compelled to sit inside his/her house for maximum time due to COVID-19, risk factor increases abruptly. In last six months almost 244 shocks were experienced in the Indian subcontinent. Thanks to technological advancement in early warning system even a slight tremor doesn't go un-noticed and advanced tele-communication system disseminates the information rapidly to the masses. Hyper active media and social increases our anxiety but we forget to focus on the remedial actions. Let us focus on the response mechanism which includes do's and don'ts before, during and after the EQ.

Though Govt. agencies through community awareness program are acquainting the citizens about predicting an imminent danger e.g. earthy smell or peculiar behavior of few animals, birds and fishes are sign of an approaching tsunami or cyclone, landslide/avalanches can be sensed by hearing the crackling sounds of trees and roaring of moving boulders. Sensing an earthquake requires additional foresightedness and observation qualities. Howling dogs are natural early warning elements but sometimes an unhappy or distressed dog can also lead to a stampede. Ants and rodents coming out of their underground habitat, or colonial migration of toads are few good examples. A giant oar fish comes out from Deep Ocean only to give us a early indication of an imminent EQ. But best amongst all is the only flying mammal "the Chiropteran" which are commonly known as "bat". Its ability to detect the magnetic field for navigation (echolocation) makes her the master of all creatures as far as earthquake early warning is concern. However the legends of vampire bats, its association with another word and more recently news of corona virus carrier make them the most hated animal of this planet.

Let us turn our attention to a realistic and practical approach for earthquake impact mitigation. Government has played its parts by enacting the national building law-1982, now it is our responsibility to adhere to the rules and regulations. Those officials and agencies whose responsibility it is to make rules must undertake their task religiously. Community also has its responsibilities and usually we neglect rules & regulations and risk lives of our loved ones for a penny. We must remember that death would come once in this life and after death all paraphernalia will remain here on this earth only. Preparedness of earthquake response is as important as the mitigation measures.

Earthquake preparedness for community:

a) Preparation before Earthquake.
b) Do's and Don'ts during the EQ
c) Do's and Don'ts after EQ

A. Preparation before an Earthquake :-

i. Identify a safe place inside the house, preferably a hard surfaced wooden table placed into a corner of the room. All family members especially kids must be aware of this 'safe haven'. Usually when I play "hide and seek" with my kids I encourage my kids to hide at those particular places which I consider safe places. I repeat it every time, I play this game with my kids to register it into the muscle memory of the kids and I hide myself at those particular places deliberately so that they follow me. That how learning can be practiced by playing.

ii. Identify the evacuation routes, "the safest or the shortest". Remember that elevator must be avoided; always use stairs after the tremors are over.

iii. Prepare a disaster management kit (a survival kit). It can be divided into two parts non-replenishable items which include whistle, torch (with extra dry batteries), radio (with extra dry batteries), a sling, a combination tool (like Swiss knife). Perishable items (food items) which must be changed before their expiry dates, these include water bottles, juice or dry food (Jiggery & Roasted chickpeas are the best option).

Disaster Management Kit

iv. Memorize the mobile/contact number of at least one living relative/friends (who lives in the same district but in different locality) so that he/she can be called in case of any eventuality.

v. Prepare a family re-union plan and make it clear to all family members by rehearsing it. During rehearsal enjoy it like a game. Remember planning is more important than an actual plan. Plan may fail but habit of planning would certainly help us in emergency situation.

vi. First aid training is a must for all citizens; unfortunately our community is lagging far behind in this area. I have seen various examples when family members of even trained rescuers could not be saved. Once a 8-9 month toddler of a rescuer slipped into toddler's pool due to negligence.

vii. The Family made efforts to search for a doctor but no pre-hospital treatment was given to him for more than 45 Minutes. The kid could not be saved even by the doctors. In a second traumatic incident a 2 year boy swallowed an almond which choked his wind pipe. In this case also, the family rushed here and there in search of a doctor but no pre-hospital treatment was given en route, consequently the kid died before reaching the hospital.

viii. Survival is a basic instinct. One should be able to transform the house hold items into rescue devices. This could include bed sheets, sari, dupatta, ropes and chairs, table etc.

ix. A study says, 50% injuries caused during the EQ are due to falling of non-structural objects (M. Patel; 2004: Research findings from 1999, Kocaeli IQ; Weekly; 0300am). Identify these objects in your house either fix or fasten it or remove it, at least those which are hanging straight on your head while sleepy.

B. Do's and Don'ts during the EQ:-

i. **DCH:-** Consider you are living in EQ Zone IV or V. Your beautifully furnished office is on second floor of the G+2 building and you don't know if your building is EQ proof or not (even if you know it is EQ resistant, your instinct will hardly rely on the architect who designed it or engineer who built it). Suddenly you feel that the earth beneath your feet is shaking. Non- structural objects are falling here and there, you are hearing the crackling sounds.. Our basic instinct would certainly guide us to run out but it won't be easy. Imagine running on the dock of a ship which is being tossed by the high oceanic waves. The better option is 'DCH' i.e. Drop, Cover and Hold. In a turbulent situation the very natural reaction of the human being is always to "duck" immediately which we have been following for thousand years ago as a hunter and gatherer. It is imprinted in our genetic memory, if not in muscle memory. I have heard soldiers gossiping about dogs and donkeys who lie on ground looking dead like a dodo when there is cross fire between Indo-Pak border guards at an isolated border out post. All major soft organs like heart, lungs and head etc are safe when we drop like a duck and cover the head with any hard object. (If nothing hard is available, cover it with both hands, protruding the elbows in upward direction). Hold anything tightly because there may be chances of injury due to rolling on ground with other sharp objects on the floor due to tremors.

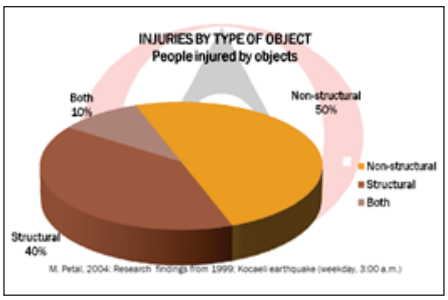

Duck, Cover, Hold

ii. Triangle of Life: -There are four basic types of collapse pattern V-shaped, cantilever, lean-to and pan cake. Survival rate varies in all different types of patterns but out of these four the chances of survival are minimum in the pan cake collapse. If we know about the "triangle of life", still there are chances of survival. "Triangle of life" is the void/gap which remains between the collapsed roof and a solid object. (That's why I mentioned earlier that 'safe haven' must be in the corner of a room adjacent to any hard object). Few pictures are self-explanatory:- Understand the theory and try to imagine those triangles in your house. Identify those places as 'safe haven'. This small but important one minute exercise may save your life.

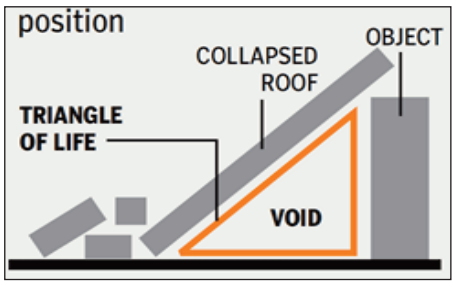

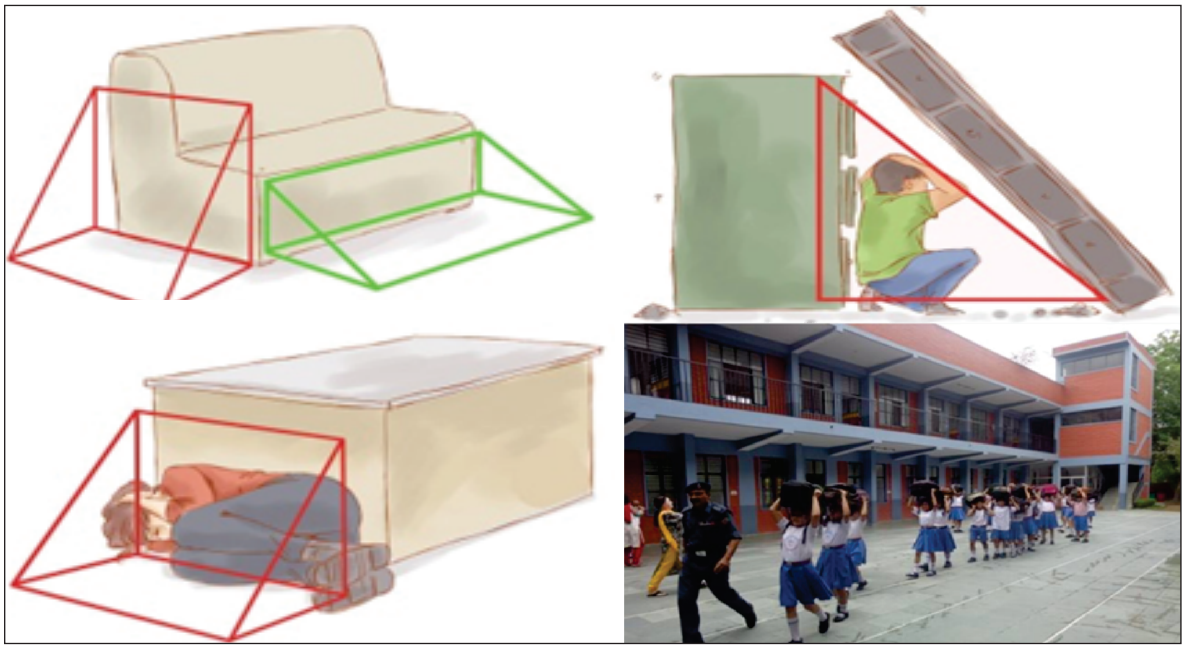

C. Do's and Don'ts after EQ:-

i. Usually earthquake tremors last up to a minute. After the tremors are over come out carefully from the hiding place (safe heaven), be careful of sharp objects. Don't react in panic since structure is unstable and there would be rubble, hard objects, broken glass pieces & hard broken building material all around. Collect the DM Kit and come out to an open area by following that pre-planned and well- rehearsed evacuation route which we have discussed already. While coming out of the building don't forget to cover the head with any hard object e.g. your briefcase, school bag, frying pan or hard cover books etc.

ii. After coming out in the open area, don't go in the vicinity of a high rise structure, electricity lines, telephone poles or trees. Remember to stay away at a distance of one and half times the length of the high rise structure.

iii. Unfortunately if trapped under debris, don't use a matchbox or lighter, rather use battery operated torch. Don't move unnecessarily and don't kick the dust. Don't panic, it saves energy and wait for the rescuers to come. As soon as you hear any noise, blow a whistle and/or knock on hard surface with some solid object.

iv. Always expect the aftershocks hence don't enter into the damaged or partially damaged structures.

v. Before and during any emergency situation listening to radio is a good practice, it keeps you updated. Govt. agencies regularly pass important instructions to the community through radios.

vi. Before entering into houses always check the fire hazard, ensure that no gas pipe line is damaged. Turn off the gas knobs; try to smell for gas leak or any other inflammable liquid. Switch on/off the light only after ensuring that no inflammable gas/liquid is leaked.

vii. Do not touch the downed poles and power lines.

viii. Help the injured and trapped surface victims only. Know your limitation & don't go beyond prescribed limit marked by the security agencies.

ix. Pay special attention to those who need special care, this includes physically challenged, sick, elderly people, infant and pregnant women.

x. Use your mobile phones/ telephones only in case of emergency; don't drain out your mobile batteries. If you are planning to leave your home before being re-united with your family members, leave a message before leaving.

Earthquake Response:-

1. Response by Community & Volunteers
2. Response by District administration & other stakeholders
3. Specialized response by NDRF

Initial unorganized response by community

1. **Response by Community & Volunteers in Search & rescue Operations: -** Community is always the first responder. Whenever there is a structure collapse due to an earthquake, immediate neighbor who is not affected by that collapse would be the first to reach to the incident site. Those victims who are wounded but not trapped deep inside the debris are called "surface victims". These surface victims can be removed by human efforts and first Aid should also be provided to these victims thereafter. Community should be trained enough to evacuate these surface victims and shifting to the ambulance after initial stabilization of their condition by giving first Aid.

Improper evacuation of surface victim by community

NDRF in its Community based capacity building programmes train volunteers e.g. Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS), Associate NCC Officers, home guard & Civil defence volunteers. Three to five days training program based on search and rescue techniques of various disasters is conducted by NDRF which would be very useful in such emergency situations. Collective tools are also procured at talluka and village level and stored at a common place e.g. a community center so that they can be used during any emergency. Initial hours after occurrence the incident is very crucial as far as lifesaving is concern, this is called as "golden hour principle". Most of the live victims are saved during these golden hours hence role of community as well as the district administration very crucial.

Response by NDRF trained volunteers

1. **Role of district administration: -** Disaster management is a state subject. DM Act -2005 lays three tier structure at national, state and district level. District Disaster Management Authority being the smallest unit plays very crucial role in disaster response. District Magistrate/ Collector being de-jure head of DDMA, is empowered to pool up any resources of the district in impending disaster situation and/or during disaster situation. It is responsibility of district administration to ensure coordination of various stakeholders e.g. fire service, police, traffic police, electricity, PWD, irrigation, food and supply, public relation office, tele-communication, health services and forest department etc. District administration must conduct regular mock exercises to achieve the desired level of cooperation and coordination among various stakeholders. Lesson learnt in the discussed in de-briefing sessions in mock exercise must not go un-noticed rather they must be addressed by district administration on priority. Disaster management plan of the district must also be amended based on gaps identified after the each mock exercises. Response by the various government agencies depends upon the preparation of the concerned departments.

Emergency Operation Centre (EOC)

The most important aspect of the response by district administration is triggering of any incident. As soon as district control room receives any information of disaster it is conveyed to all concern. Emergency operation center (EOC) is activated immediately. Incident Commander must present himself at Incident Command Post (ICP).Responsible officer must ensure that all sections, branches and units of Incident Response System (IRS) get activated immediately. All Emergency Support Functions (ESF) must present at designated Staging Area with their full potential.

2. **Specialized response by NDRF:-** In section 44 (i) of chapter VII of DM act 2005, a statutory provision for the constitution of the National disaster response force; 'a specialized force' to respond to disaster/ threatening disasters. Resulting which a multi-disciplinary, multi-skilled, Hi-tech specialized force was raised in 2006 initially with 8 battalions and at present there are 13 battalions located in various part of the country based on the vulnerability profile of India.

Briefing at staging area & formation of Emergency Response Teams (ERTs)

Each NDRF unit keep ready its two teams for any emergencies. Team personnel gather at common given place with their personal luggage. Popularly known as "angles in orange" each NDRF unit is equipped with 310 state of the art equipment. Apart from this each Search & Rescue team has a canine search element. Each team has 47 highly trained specialized rescuers. Authorized equipment for one team is always kept loaded inside the truck. Unit has a 24x7 manned control room which receives information through news (electronic media) or direct requisition from the concerned district. Teams are

alerted immediately. Control room corroborates the information and teams are sent to the incident site after the initial briefing by Deputy Commandant (Operation), who is responsible for induction & de-induction of the teams. On reaching the incident site team commander fetch information from incident commander & locals present there so that he can plan the operation to save more lives. Team commander along with safety officer do the initial assessment of the given work site. Simultaneously team establishes the Incident Command Post.

Team conduct search by the canines, equipment and physical. After locating the victim, debris is removed by lifting and rigging. After shocks area a major hazard for rescuers. Since structure is already unstable, team tries to minimize the risk by shoring. It is done by wooden blocks and pneumatic shoring system. Though risk is minimized only we cannot rule out the possibility of collapse of structure completely by these shoring methods.

Canine search by NDRF team

It's the call of duty, strict discipline & feeling to serve the community which keeps motivated the rescuers to work in such adverse situation.

Specialised response by NDRF rescuers

After clearing the debris building material is chipped or cut by equipment which at par with international standard as far as technology is concern. Rescuer reaches to the victim and stabilizes the condition of the victim on the stretcher inside the rubble only. Victim is transported to hospital in the ambulance. Lots of lives have been saved by the NDRF rescuers and thousand dead bodies have been extricated till date. NDRF is world largest force which is dedicated to disaster response only.

There are universal guidelines which are being followed by citizen of any country. No special training and equipment are required. Only common sense and presence of mind is enough to save the precious life.

Remember that community is always the first responder. When any disaster strikes and relief arrives there is a period of complete chaos. This is a crucial time and maximum lives can be saved during this time. Strive hard to survive rather than cursing the rescue agencies or local government bodies which are already hard pressed, sometimes even they have lost their family members too.

High rise rescue by NDRF rescuers

TRAINING ACTIVITIES OF CDTI, GHAZIABAD

Training courses conducted by CDTI, Ghaziabad from April to June, 2021:-

1. **"Terrorist Funding" from 12.04.2021 to 16.04.2021**

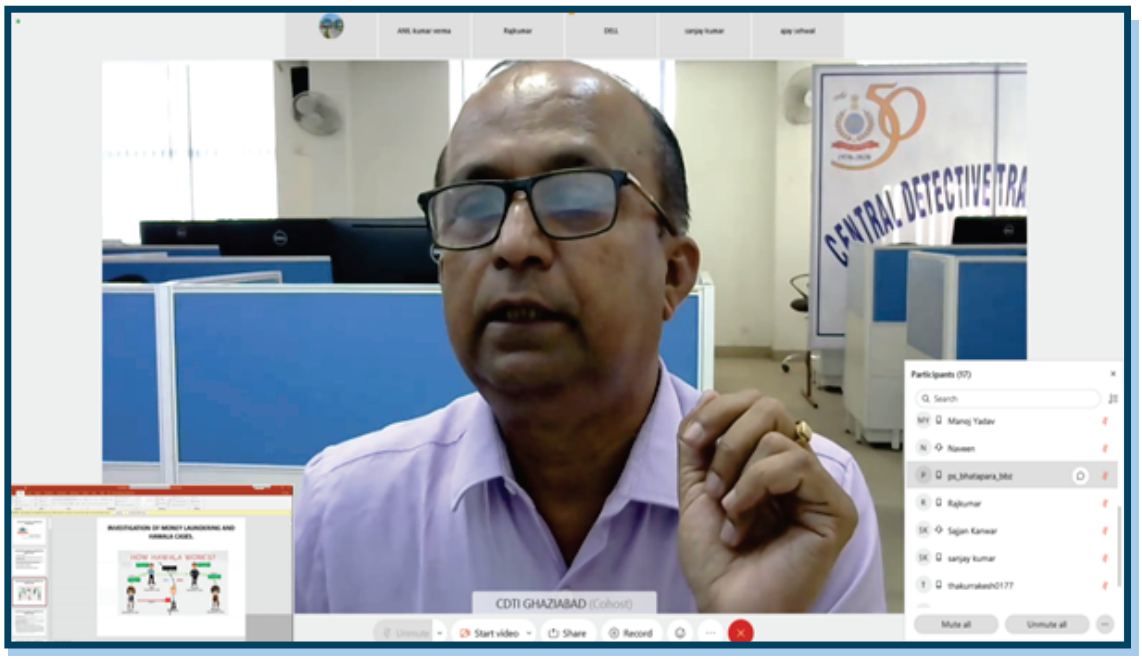

2. "Investigation of Crime against Women & their safety related issues" from 19.04.2021 to 23.04.2021

3. "VIC on Forensic Science and Investigation Techniques" from 26.04.2021 to 28.04.2021.

4. **"Investigation of Crime against Children (NCPCR)" from 26.04.2021 to 30.04.2021**

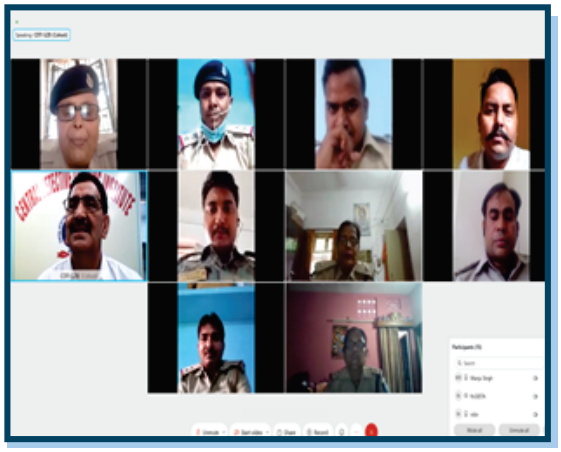

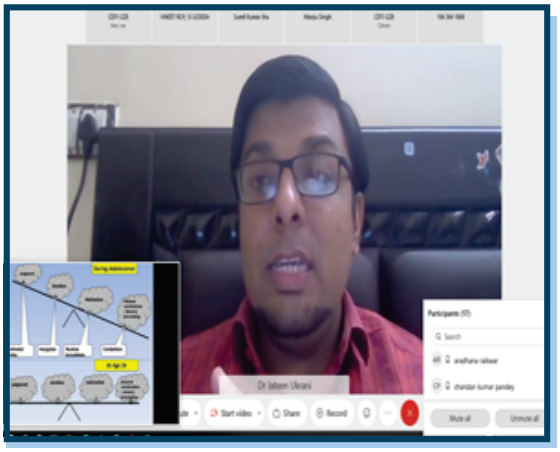

5. "Radicalization and De-Radicalization" from 03.05.2021 to 05.05.2021

6. "Collection and analysis of Technical Intelligence" from 03.05.2021 to 07.05.2021.

7. "Station House Management" from 10.05.2021 to 12.05.2021

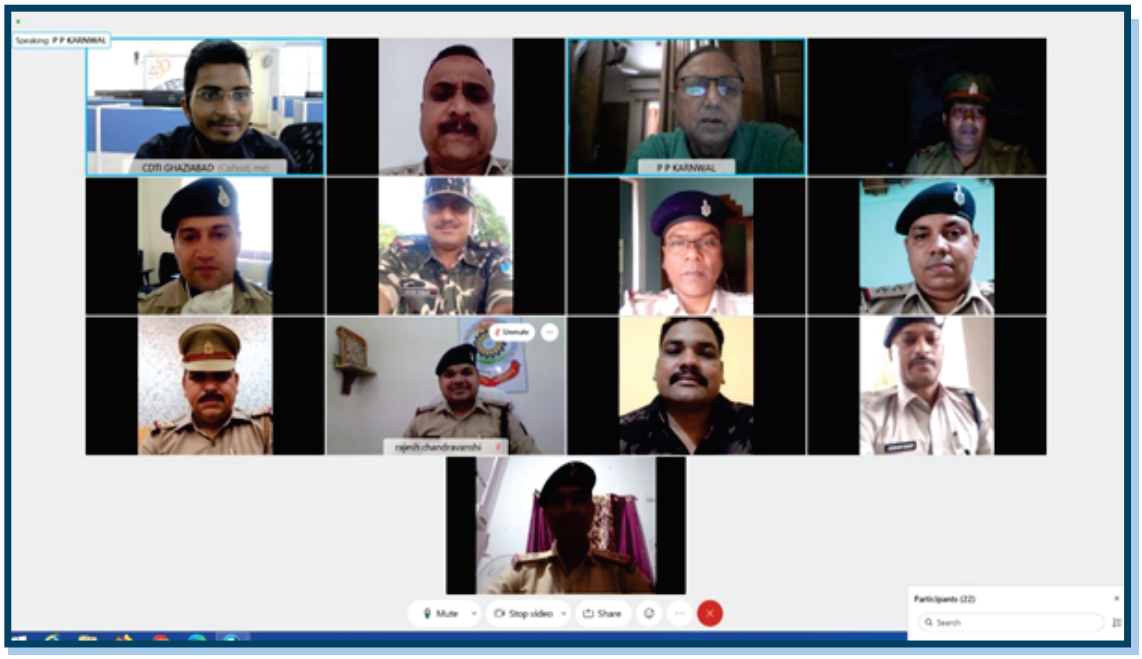

8. VIC on "Forensic Science and Investigation Techniques" from 10.05.2021 to 12.05.2021

9. "Capacity Building and Perception Management for women Police Officers" from 17.05.2021 to 21.05.2021.

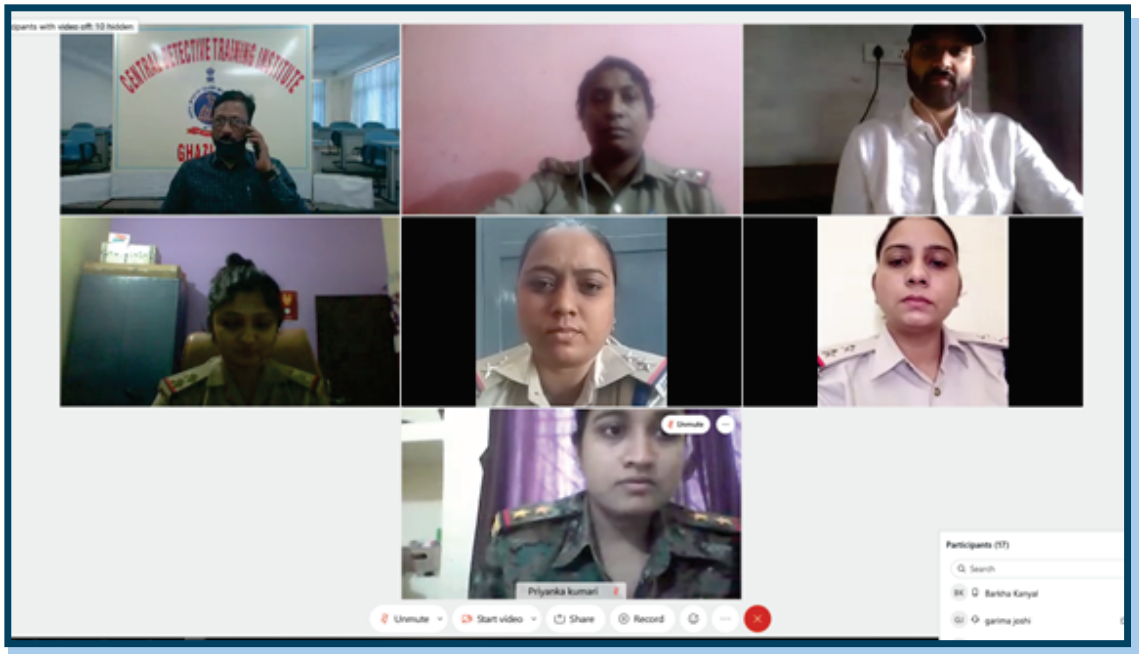

10. "Handling of Terrorist Financing and FICN Cases" from 17.05.2021 to 21.05.2021

11. “Integrated course for Forensic Science and Investigation for Police Officers and Prosecution Officers”from 24.05.2021 to 28.05.2021

12. “Investigation of Organised Terror Crime” from 24.05.2021 to 28.05.2021

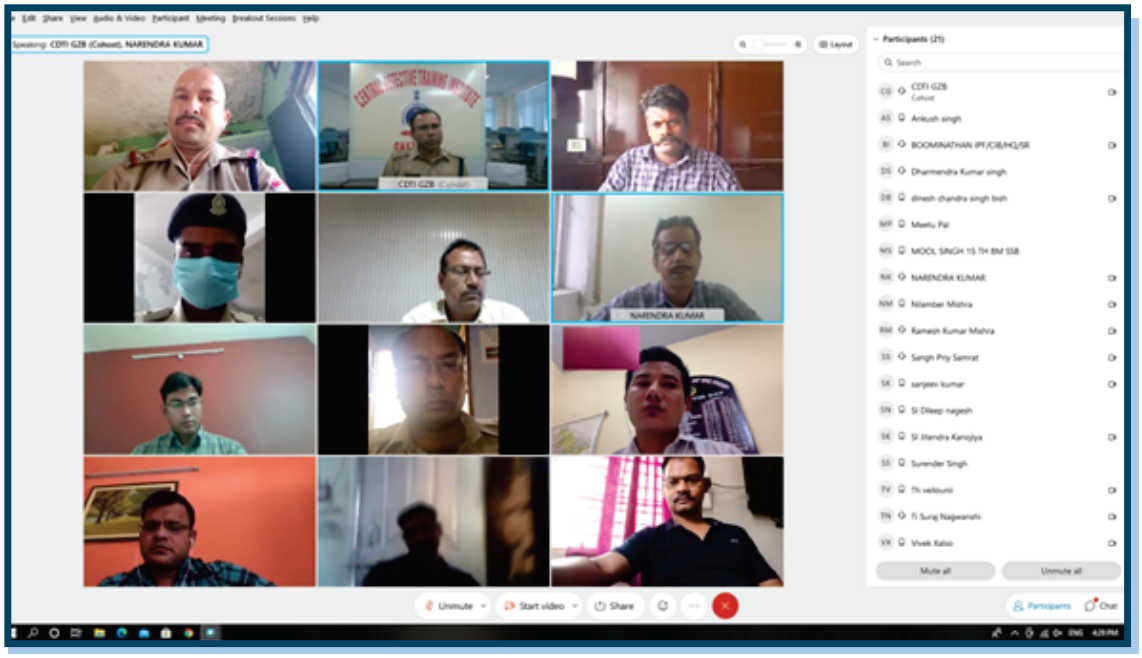

13. “Use of Videography/Photography” from 31.05.2021 to 02.06.2021

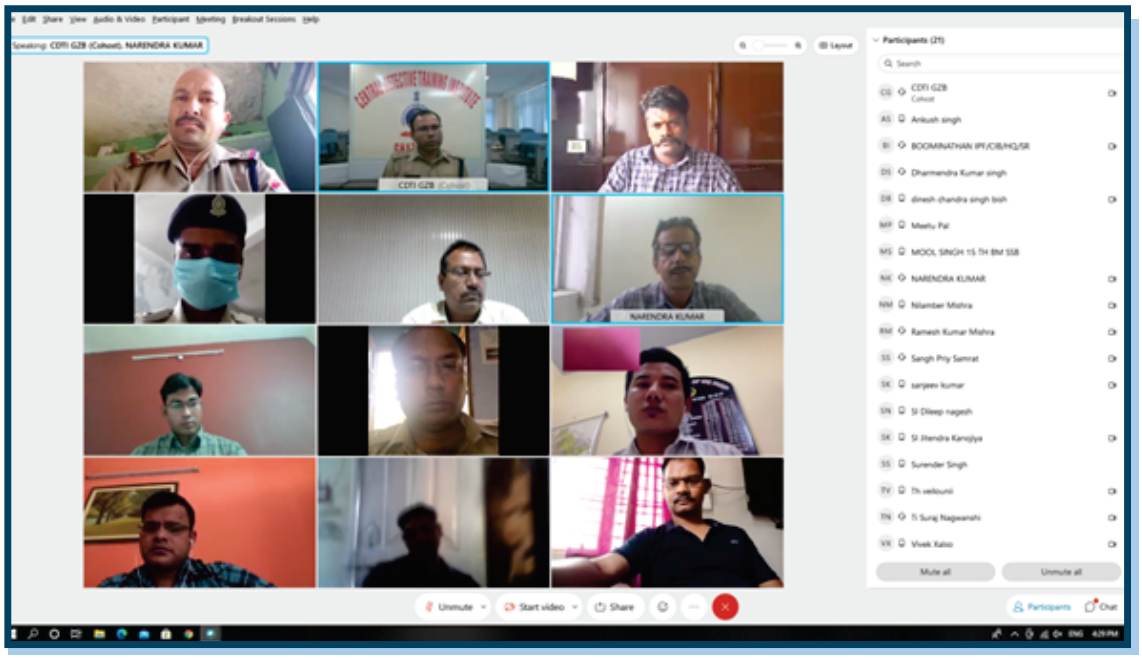

14. “Investigation of Crime against Children (NCPCR)” from 31.05.2021 to 04.06.2021

15. “Investigation of NDPS cases” from 07.06.2021 to 11.06.2021

16. **"Investigation Abroad/Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT)" from 07.06.2021 to 11.06.2021**

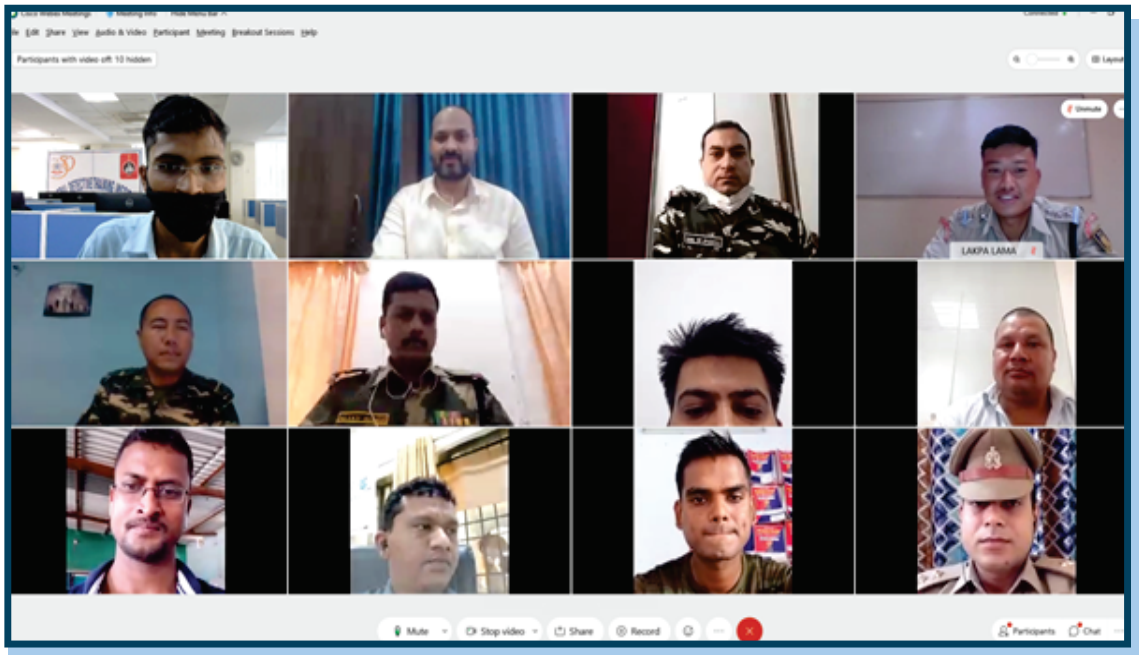

17. "Cyber Crime and Cyber Law awareness for Public Prosecutors and Judicial Officers" from 14.06.2021 to 16.06.2021

18. "Post Blast Investigation" from 14.06.2021 to 18.06.2021

19. "Mobile Forensic" from 21.06.2021 to 23.06.2021

20. "Countering Cyber Terrorism" from 21.06.2021 to 25.06.2021

21. "Investigation of Crime against Women & their Safety related issues" from 28.06.2021 to 02.07.2021

22. "New Challenges in Countering Cyber Terrorism" from 28.06.2021 to 02.07.2021

Other Activities

World Health Day Programme

Central Detective Training Institute, Ghaziabad observed World Health Day by organizing a workshop on the subjectat its campus on 7th April, 2021. On this occasion, Shri Virendra Kumar, Vice Principal of the institution first highlighted about the importance of this day. After this, Dy.SP, Shri Vijendra Pal Sharma, expressed his views regarding eradication of various diseases and pandemics such as Smallpox, Polio eradication campaign, Meningitis, HIV AIDS, Malaria and Tuberculosis etc. Further also explained and informed about the guidelines issued by the World Health Organization and Government of India in relation to the prevention of global epidemic Covid-19 and about vaccination for corona. Apart from this, other speakers also expressed their views about cleanliness and healthy lifestyle on this occasion.

तीनअर्द्धदिवसीय हिंदी कार्यशाला

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नेतृत्व में केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, गाजियाबाद में कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए दिनांक 14.06.2021 से 16.06.2021 तक तीन अर्द्धदिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन संस्थान के निदेशक श्री अम्बर किशोर झा, भा.पु.से. द्वारा किया गया। कार्यशाला के प्रथम दिवस पर श्री बृज कुमार दुबे, सहायक निदेशक (राजभाषा), केन्द्रीय माल एवं सेवा कर कार्यालय, गाजियाबाद ने 'यूनिकोड के माध्यम से हिंदी टाइपिंग की जानकारी और अभ्यास तथा विंडो–10 के माध्यम से हिंदी अनुवाद की जानकारी व अभ्यास' विषय पर जानकारी प्रदान कीद्य इसके अतिरिक्त, इस संस्थान के हिंदी प्रभारी अधिकारी, श्री बीरेन्द्र कुमार के द्वारा' हिंदी के प्रचार–प्रसार हेतु हिंदी प्रोत्साहन योजना की जानकारी, कार्यालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग व तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने संबंधित जानकारी, कार्यालय में टिप्पण एवं लेखन तथा विभिन्न प्रकार के पत्राचार की जानकारी एवं अभ्यास' हेतु प्रशिक्षण दिया गया।

"भारतीय एकता के लक्ष्य का साधन हिंदी भाषा का प्रचार है।"

– टी. माधवराव

सिविल पुलिस के साथ कोरोना टीकाकरण जागरूकता अभियान

दिनांक 15.06.2021 को इस संस्थान के पुलिस उपाधीक्षक श्री रमन पाल सिंह, निरीक्षक ओमप्रकाश व निरीक्षक नजमुल शाकिब ने थाना बापूधाम, गाजियाबाद पर थाना प्रभारी निरीक्षक अमित खारी की मौजूदगी में थाने पर मौजूद समस्त स्टाफ को कोरोना वैश्विक महामारी के टीकाकरण के बारे में जागरूक किया व सभी को शत प्रतिशत टीकाकरण कराने हेतु प्रोत्साहित किया।

Webinar on Women Safety

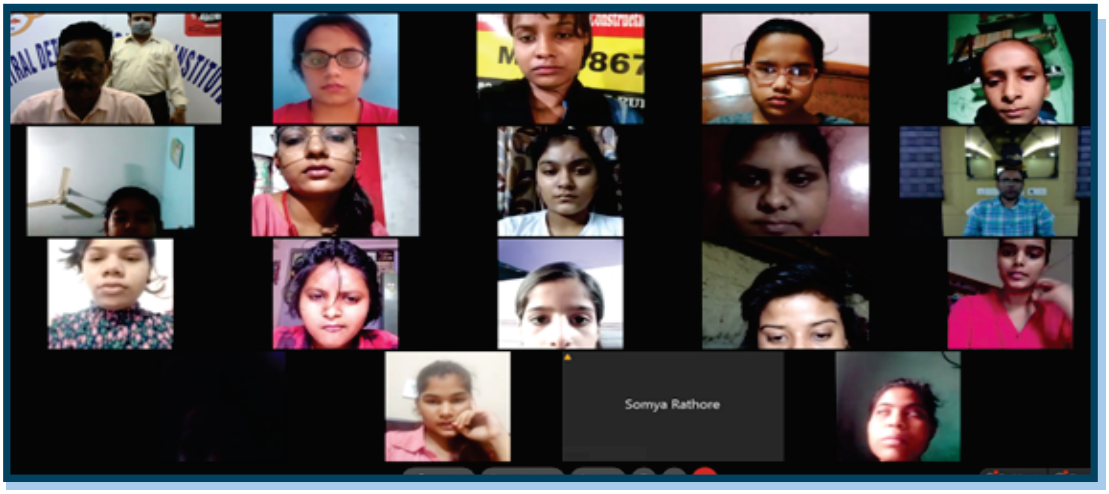

Central Detective Training Institute, Ghaziabad organized a webinar on "Women Safety" on 17.06.2021to bring awarenessamong the girl students of various schools and medical college about the women safety and cyber-crime.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम

दिनांक 21.06.2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें संस्थान के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, गाज़ियाबाद

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
सेक्टर–19, कमला नेहरू नगर, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201002
फैक्स / दूरभाष : 0120–2986732
ई–मेल : pplcdtsgzb@bprd.nic.in